भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 2599

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

विभिन्न निगमों/एसपीवी के ऋण का पुनर्गठन

2599. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने विभिन्न निगमों या उनके विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के ऋण के पुनर्गठन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ताकि इसके स्वामित्व वाले निगमों/एसपीवी को दिए गए ऋणों के पुनर्गठन के लिए संबंधित वित्तीय संस्थानों को उचित निर्देश जारी किए जा सकें और अब इनका भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निगम और एसपीवीवार आज तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) द्वारा उठाए गए ऋणों के पुनर्गठन के संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसका भुगतान कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई स्कीम के अंतर्गत राज्य समेकित निधि से किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेलंगाना राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड (केआईपीसीएल), तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड) और आरईसी लिमिटेड द्वारा क्रमशः 37,737.11 करोड़ रुपये और 30,536.08 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ वित्तपोषित किया गया था।

राज्य सरकार को आगे सूचित किया गया कि ये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) घरेलू और अपतटीय बाजारों में विभिन्न स्रोतों से धन जुटाती हैं। उधार लेने की

अपनी लागत के आधार पर, वे उधार दरों का निर्धारण करते हैं, जो उधार लेने वाले की ग्रेडिंग पर भी निर्भर करता है। परियोजनाओं के पूरा होने/बंद होने पर ब्याज दर में किसी भी छूट पर विचार किया जाता है। हालांकि, ऋण परिशोधन अनुसूची में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएफसी/आरईसी लिमिटेड की बुक में केआईपीसीएल के खाता वर्गीकरण (मानक से उप-मानक तक) में गिरावट आएगी।

*****